Demand to include 16 Castes of Uttar Pradesh in SC Category

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आपक माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कश्यम, कहार, केवट, निषाद, बिन्द, भर, प्रजापति, राजभर, वाथम, गौड, तुराहा, माझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर और महुआ जातियां आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा रोज़गार के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों की अति पिछड़ी दशा के कारण उनके साथ आज भी छुआछूत किया जाता है। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपमान का जीवन व्यतीत करने वाली इन समस्त जातियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि इन उपरोक्त सभी 16 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर उन्हें मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएं ताकि ये सभी जातियां राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें, परंतु खेद है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे हैं। फिर भी केन्द्र सरकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मौन बरती हुई है जिसके कारण उत्तर प्रदेश की इन सभी 16 जातियों, जिनकी आबादी करोड़ों में है, में आक्रोश व्याप्त है और कभी भी राजस्थान के गुर्जर आंदोलन की तरह स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की करोड़ों की आबादी वाली इन 16 जातियों को शीघ्रता से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की कृपा करें तथा अनुसूचित जातियों का कोटा भी बढ़ाया जाए, ताकि उपर्युक्त सभी 16 जातियों को इसमें शामिल किया जा सके और उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास किया जा सके।

Demand to Ban FDI in Retail Sector

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the Government about the impending negative reaction by allowing Foreign Direct Investment in retail sector. Our country is already facing double digit inflation rate, and consequently the prices of essential commodities are higher than ever before. Inline trading of essential commodities, black marketing, illegal storage of commodities, middlemen role between farmers and to the consumers are the basic reasons for the high prices of food items. Our former Chief Minster of